8 जनवरी 2026
गुरुवार

केशव टाइम्स

डिजिटल संस्करण

जमीन विवाद में रक्तरंजित हुआ सिकरौल, अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत, तीन जख्मी, चार गिरफ्तार

2

प्रमुख खबरें : दिल्ली ■ पटना ■ बक्सर ■ शाहाबाद ■ मगध ■ सारण ■ मिथिलांचल ■ चंपारण ■ पूर्वांचल ■ लखनऊ

आपकी आवाज

एक नजर

दिल्ली समेत उत्तर भारत में सूखी सर्दी का अजीब मिजाज

नई दिल्ली। कभी घने कोहरे की धुंधली सुबह, कभी दोपहर में खिलखिलाती तेज धूप और शाम होते ही बर्फीली हवाओं की चुभन। उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम मानो आंख-मिचौली खेल रहा है। ठंड जरूर महसूस हो रही है, लेकिन हालात न पूरी तरह कोल्ड डे के हैं और न ही कोल्ड वेव जैसी सख्ती दिख रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद सर्दी पीछा नहीं छोड़ रही, जिसकी वजह उत्तर-पश्चिम से चल रही ठंडी और बर्फीली हवाएं हैं। दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यह अजीब मिजाज लोगों को उलझन में डाल रहा है। कभी घना कोहरा छा जाता है, तो कभी बिल्कुल साफ आसमान नजर आता है। दिन में धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड तेजी से बढ़ जाती है।

भाजपा और सहयोगियों के बीच सीटों का समझौता

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को जानकारी दी कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात का उद्देश्य राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए के सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल पर चर्चा करना था। मीडिया से बातचीत में सरमा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 15 फरवरी तक असम गण परिषद (अगप) और अन्य सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि मौजूदा सहयोगियों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने का कार्य 15 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सीटों का बंटवारा और गठबंधन से जुड़े अन्य विवरण 15 फरवरी तक तय हो जाएंगे। कल रात मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर इस पर विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान बीपीएफ प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी भी मेरे साथ थे।" उन्होंने आगे बताया कि इस बैठक से पहले यूपीपीएल अध्यक्ष प्रमोद बोरो ने भी शाह से मुलाकाल की थी।

सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर बड़ा फैसला, मैरिट सबके लिए

- आरक्षित उम्मीदवार मेरिट पर जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे
- जनरल श्रेणी जाति नहीं, बल्कि योग्यता पर आधारित है
- आरक्षण लाभ लेने पर यह नियम लागू नहीं होगा

एजेंसी। नई दिल्ली

आरक्षण पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जनरल या ओपन कैटेगरी में चयन मेरिट के आधार पर होगा। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल श्रेणी की कट-ऑफ से अधिक नंबर लाता है, तो उसे जनरल कैटेगरी में भी गिना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जनरल श्रेणी किसी जाति विशेष की नहीं है, बल्कि मेरिट के आधार पर तय की जाती है। अदालत के इस फैसले का सामान्य वर्ग समेत ओबीसी, एसी-एसटी व और ईडब्लूएस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो जनरल श्रेणी की कट-ऑफ से अधिक अंक लाते हैं, उन्हें मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में शामिल किया जा सकेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल श्रेणी किसी जाति विशेष की नहीं, बल्कि योग्यता पर आधारित है। यह फैसला ओबीसी, एसी-एसटी व और ईडब्लूएस सहित सभी वर्गों पर असर डालेगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षित वर्ग का कट-ऑफ जनरल से ज्यादा हो और आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल कट-ऑफ पार करता है, तो जनरल कोटे में उसका चयन किया जा सकता है। जनरल कैटेगरी में सभी मेधावी छात्रों को जगह मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, जनजाति, वर्ग या लिंग का हो। कोर्ट का कहना है कि फॉर्म में अपनी जाति लिख देना अपने आप में आरक्षित सीट पाने का अधिकार नहीं देता, बल्कि सिर्फ यह बताता है कि उम्मीदवार आरक्षित सूची में भी दावेदार हो सकता है।

कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर

सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में साफ किया था कि मेधावी उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर मौका मिलना चाहिए। अदालत के नए आदेश से इसपर फिर से मुहर लग गई है। जनरल कट-ऑफ से ज्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भी सामान्य कैटेगरी में शामिल किया जा सकेगा। अगर उम्मीदवार ने परीक्षा के किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया है, तो उसपर ये नियम लागू नहीं होगा और उसे सामान्य वर्ग में नहीं गिना जाएगा। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर बिना छूट जनरल कट-ऑफ पार करता है, तो जनरल सीट पर ही उसका चयन किया जाएगा। कोर्ट के अनुसार, इस फैसले से मेरिट के नियमों को मजबूती मिली है। इससे जनरल उम्मीदवारों के किसी भी अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। अगस्त 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने 2756 पदों (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-2) के लिए भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा के नतीजों ओबीसी, एसी-एसटी व और ईडब्लूएस का कट-ऑफ जनरल से ज्यादा चला गया था। कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने जनरल कट-ऑफ पार किया, लेकिन अपनी कैटेगरी का कट-ऑफ न होने के कारण उन्हें अगले राउंड से बाहर कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में नतीजों को चुनौती दी गई, जिसपर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जनरल लिस्ट मेरिट के आधार पर तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस फैसले पर मुहर लगा दी है।

1 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना-2027

एजेंसी। नई दिल्ली

देश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि 30 दिनों के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्व-गणना कराने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में कराई जाती है। इसके हिसाब से 2021 में जनगणना कराई जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। देश की जनसंख्या की गणना करने का यह विशाल अभियान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा - अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना और फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना।

मोदी के नेतृत्व की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की

ट्रंप के दबाव में झुके मोदी : राहुल गांधी

- ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ का भी जिक्र किया है जिससे दबाव बढ़ा

एजेंसी। नई दिल्ली

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर दबाव में आकर झुकने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मोदी के नेतृत्व की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। राहुल गांधी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था। ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना है कि भारत सरकार अब बहुत ज्यादा टैरिफ दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद काफी कम कर दी है।राहुल गांधी ने कहा कि मैं इन बीजेपी-आरएसएस वालों को अब बहुत अच्छे से जानता हूं। उन पर थोड़ा दबाव डालो, थोड़ा धक्का दो और वे डर के मारे भाग जाते हैं।ह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी ट्रंप के इशारे पर झुक गए जबकि 1971 के युद्ध मंए तब की पीएम इंदिरा गांधी अमेरिकी धमकी के आगे बिल्कुल झुकी नहीं।

ट्रंप के इशारे पर मोदी ने किया सरेंडर

राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया। उन्होंने फोन उठाया और कहा कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया और हां सर कहकर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 1971 के युद्ध से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक समय अमेरिका के दबाव के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा था। उन्होंने अमेरिका के सेवंथ फ्लीट का जिक्र करते हुए कहा, श्आपको शायद वह समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था। सातवां बेड़ा आया था। 1971 के युद्ध में, सातवां बेड़ा आया, हथियार आए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर आया। इंदिरा गांधी जी ने कहा, श्मुझे जो करना है, मैं वही करूंगी।, बीजेपी वालों और कांग्रेस में यही फर्क है।श असल में, ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने की वजह से 25 प्रतिशत टैक्स भी शामिल है। ट्रम्प ने कहा कि मेरे उनके (मोदी) साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वह मुझसे बहुत खुश नहीं हैं क्योंकि अब उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। उन्होंने रूस से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। अगस्त में लगाए गए इन टैरिफ की वजह से कई दौर की ट्रेड बातचीत हुई है और दोनों नेताओं के बीच कम से कम चार बार बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी की बात कही है, और दावा किया कि नई दिल्ली पांच साल से इन विमानों का इंतजार कर रही है।

कांग्रेस ने 5 राज्यों में वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस ने भूपेश बघेल, सचिन पायलट, डीके शिवकुमार से लेकर मुकुल वासनिक जैसे अपने वरिष्ठ नेताओं को असम, केरल तथा पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन पांच में से कांग्रेस कम से कम दो राज्यों केरल तथा असम में लंब अर्से बाद सत्ता में वापसी की अपनी संभावनाएं देख रही है। कांग्रेस ने इन राज्यों में उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमिटी का पिछले हफ्ते गठन करने के बाद चुनावी पर्यवेक्षकों की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और बंधु तिर्की को असम का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।वहीं कांग्रेस महासचिव तथा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार और केजे जार्ज को केरल का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव के लिए मुकुल वासनिक के साथ तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेडडी तथा काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल में सुदीप राय बर्मन के साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी और बिहार के शकील अहमद खान को वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है।

रूसी झंडे वाले टैंकर पर अमेरिका का कब्जा

एजेंसी। वाशिंगटन

वेनेजुएला पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को नाम न छापने की शर्त पर इस कार्रवाई की जानकारी दी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कई हफ्तों तक पीछा करने के बाद रूस के झंडे वाले तेल टैंकर को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया है।नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए अधिकारी ने संवेदनशील सैन्य अभियानों पर चर्चा की। अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने पोत को जब्त कर लिया और उसका नियंत्रण कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दिया। बता दें कि अमेरिका पिछले महीने से ही उस टैंकर का पीछा कर रहा था, जब उसने वेनेजुएला के आसपास प्रतिबंधित तेल जहाजों पर अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की थी।सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिकी यूरोपीय कमान ने पुष्टि की है कि अमेरिकी तटरक्षक बल के कटर मुनरो ने जहाज को जब्त करने से पहले 'अमेरिकी संघीय अदालत द्वारा जारी वारंट के तहत' उसका पीछा किया था। बता दें कि कटर मुनरो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और खोज व बचाव जैसे मिशनों के लिए इस्तेमाल होता है।यह जहाज 2024 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, उस पर आरोप था कि यह लेबनानी आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला से जुड़े एक कंपनी के लिए तेल तस्करी कर रहा था।

ST. JOHN SECONDARY SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, +2 Level
KALI NAGAR DUMRAON (BUXAR)
FREE ADMISSION 2026-27
Salient Features
- Digital Classes.
- Online Classes.
- Erp Facilities.
- Olympiad Exam.
- Organizational Skills.
- Art Gallery Library.
- Transport Facility.
- Career Preparation.
- Expert Teachers.
- Extra Classes.
- CCTV Surveillance
- Co Curriculum Activities.
Our Institutions:-
ST. JOHN SECONDARY SCHOOL
Ramdhati Mod, Karnamepur +91 7488782349 | KORANSARAI +919199315755 | KALI NAGAR, DUMRAON +91 7909000372, 9472394007

संगम सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल
परामर्श शुल्क मात्र ₹ 1/-
- जनरल फिजिशियन
- स्त्री रोग विशेषज्ञ
- जनरल व गेस्ट्रो सर्जरी
- बाल रोग विशेषज्ञ
- नाक, कान, गला विशेषज्ञ
- हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ
- न्यूरो फिजिशियन व सर्जरी
- हृदय रोग विशेषज्ञ
- ओनको सर्जरी (कैंसर)
- यूरोलॉजी सर्जरी
- फिजियो थेरेपी सेन्टर
- पैथोलॉजी
Add.: 53/2, Avadhpuri Colony, Khargapur, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 | Email : Sangamhospitals2025@gamil.com
Mob.: 9956026260, 9044872872

हत्या के बाद एक्शन मोड में आए बक्सर एसपी शुभम आर्य त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम की गठन

जमीन विवाद में रक्तरंजित हुआ सिकरौल, अंधाधूंध फायरिंग में एक की मौत, तीन जख्मी, चार गिरफ्तार

- विवादित जमीन पर धान काटने के दौरान हुई हिंसक झड़प, पूर्व से सूचना के बावजूद घटना के बाद पहुंची पुलिस
- 30-40 वर्षों से चल रहा था विवाद, पूर्व में मृतक के पिता की भी हुई थी हत्या, स्वजन पुलिस पर लगा रहे है लापरवाही के आरोप

केटी न्यूज/डुमरांव

अनुमंडल के सिकरौल थाना क्षेत्र के भखवा गांव में जमीन विवाद में बुधवार की दोपहर अंधाधुध फायरिंग हुई। जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना शाम चार बजे की है। इसकी जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है तथा मामले की जांच, जख्मियों के इलाज व आरोपितों की धर-पकड़ में जुट गई है। देर शाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब घटना में प्रयुक्त असहले ही पड़ताल कर रही है। खुद पुलिस कप्तान शुभम आर्य मौके पर कैंप कर रहे है।

मृतक की पहचान संजय कुमार चौबे उम्र 50 वर्ष पिता स्व. शिव शंकर चौबे के रूप में हुई है, जबकि जख्मियों में धनंजय चौबे पिता स्व. शिव शंकर चौबे, दरोगा चौबे पिता स्व. काशीनाथ चौबे तथा मोहन चौबे पिता स्व. भोला चौबे शामिल है। तीनों को लाठी-डंडे से चोट लगी है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया था, लोग बधार से भाग अपने घरों में छिप गए थे। बताया जा रहा है कि यह विवाद खेत से धान काटे जाने के दौरान हुआ।

घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित एक सफेद रंग की स्कार्पियों पर सवार हो डुमरांव की तरफ भाग निकले है। ग्रामीण सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद गांव में जबदस्त तनाव कायम है। हालांकि, पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भखवा के कन्हैया चौबे व संजय चौबे के परिवार के बीच लगभग 30-40 सालों से छह एकड़ जमीन के लिए विवाद चल रहा था। जिसमें तीस साल पूर्व इसी भूखंड के विवाद में स्व. शिव शंकर चौबे की गोली मार कर हत्या की गई थी। उसी में बड़क चौबे व कन्हैया चौबे जेल से सजा काट कर लगभग एक साल पूर्व लौटे थे। वहीं उस जमीन पर संजय चौबे के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसके बाद बुधवार को बड़क चौबे, गणेश चौबे, कन्हैया चौबे, बलिराम चौबे व विद्यासागर चौबे धान काटने के लिए पहुंचे थे। जिसका विरोध करने संजय चौबे व अन्य लोग पहुंचे थे कि प्रशासन के आने पर धान कटेगा। उसी दौरान बड़क चौबे, कन्हैया चौबे व अन्य लोगों के द्वारा गोलीबारी व लाठी-डंडे से हमला कर दिया। जिसमें तीन लोग घायल हो गये। उन्हें सदर अस्पताल बक्सर लेकर आया गया। जहां डाक्टरों ने संजय चौबे को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो लोगों धनजय चौबे पिता स्व शिव शंकर चौबे, दरोगा पिता स्व. काशी नाथ चौब, मोहन चौबे पिता स्व. भोला चौबे का ईलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इनका लाठी-डंडे से सिर में चोट लगी है। वहीं, स्वजनों ने इस मामले में सिकरौल थानाध्यक्ष पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए है। परिजनों का कहना है कि पुलिस मर्डर होने के बाद आई है, जबकि थानेदार को घटना से पहले कई बार सूचना दिया जा चुका था कि झगड़ा होने की आशंका है। उसके बाद भी समय से पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी थी। स्वजनों का कहना है कि यदि पुलिस टीम समय से मौके पर पहुंचती तो गोलीबारी की घटना को रोका जा सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डुमरांव एसडीपीओ पोलस्त कुमार समेत कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है।

एसपी शुभम आर्य ने संभाला कमान, स्वयं पहुंचे घटनास्थल

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सिमरी थाना क्षेत्र से गणेश चौबे, वशिष्ठ चौबे, जागबली चौबे तथा नया भोजपुर से कन्हैया चौबे को पुलिस ने पकड़ लिया है। खुद एसपी शुभम आर्य घटना स्थल पर कैंप कर रहे है। आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब असलहे की बरामदगी में जुट गई है। मौके से पुलिस की टीम को एक खोखा बरामद हुआ है।

सिकरौल थाना क्षेत्र के भखवा गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, तीन लोग लाठी-डंडे की चोट से जख्मी है। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

शुभम आर्य, एसपी, बक्सर

बक्सर में रोजगार का सुनहरा अवसर, 9 जनवरी को लगेगा एकदिवसीय नियोजन शिविर

- 50 पदों पर होगा त्वरित चयन, 15 से 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन की संभावना

केटी न्यूज/बक्सर

जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक अहम अवसर सामने आया है। प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नियोजनालय, बक्सर द्वारा 9 जनवरी को एकदिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें नौकरी के लिए बाहर भटकना न पड़े।

यह रोजगार शिविर संयुक्त श्रम भवन परिसर स्थित आईटीआई मैदान, बक्सर में आयोजित किया जाएगा। शिविर का संचालन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाई एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड द्वारा विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

नियोजन शिविर में प्रशिक्षु टीम सदस्य के कुल 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के अनुसार प्रतिमाह 15 हजार से 20 हजार रुपये तक वेतन दिए जाने की संभावना है। इन पदों के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे।

प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि शिविर में अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर मौके पर ही किया जाएगा। इसके लिए जिला नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य रखा गया है। जो अभ्यर्थी अब तक निबंधित नहीं हो सके हैं, वे राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को शिविर के दिन अपना बायोडाटा एवं आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। नियुक्ति से संबंधित सभी शर्तें एवं नियम संबंधित नियोजक कंपनी द्वारा तय किए जाएंगे। जिला नियोजनालय की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में केवल सुविधा प्रदाता की होगी।

प्रभारी पदाधिकारी ने जिले के सभी शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस रोजगार शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस अवसर का लाभ उठाकर अपने भविष्य को सशक्त बनाएं।

शहरी वंशावली की उलझन खत्म, अब अंचल कार्यालय बनेगा एकमात्र केंद्र

- राज्य सरकार के फैसले से जमीन-जायदाद और उत्तराधिकार मामलों में आएगी रफ्तार

केटी न्यूज/डुमरांव

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए वंशावली को लेकर वर्षों से चली आ रही असमंजस की स्थिति पर आखिरकार विराम लग गया है। राज्य सरकार के ताजा प्रशासनिक निर्णय के बाद अब नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के नागरिकों को वंशावली के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल द्वारा जारी आदेश के तहत शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने का अधिकार अंचलाधिकारियों को दे दिया गया है। यह व्यवस्था पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

एक आदेश, कई समस्याओं का समाधान

अब तक ग्रामीण इलाकों में वंशावली सरपंच द्वारा जारी की जाती थी, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग नगर निकाय और अंचल कार्यालयों के बीच उलझे रहते थे। इस भ्रम का सीधा असर जमीन, उत्तराधिकार, दाखिल-खारिज, बैंक ऋण, बीमा दावा और न्यायालयीन मामलों पर पड़ता था। कई मामलों में वर्षों तक प्रक्रिया अधर में लटकी रहती थी। नए आदेश ने इस प्रशासनिक खालीपन को भरते हुए साफ कर दिया है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली अब केवल अंचलाधिकारी ही जारी करेंगे।

अंचल कार्यालय से मिलेगी पारदर्शिता

राजस्व विभाग का मानना है कि अंचल स्तर से वंशावली जारी होने पर सत्यापन की प्रक्रिया अधिक मजबूत होगी। अंचलाधिकारी के पास खतियान, खेसरा, नक्शा और अन्य राजस्व अभिलेख पहले से उपलब्ध रहते हैं, जिससे पारिवारिक विवरण की जांच आसान और भरोसेमंद हो सकेगी। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि फर्जी दस्तावेजों पर भी प्रभावी रोक लगेगी। एक ही सक्षम अधिकारी के पास अधिकार होने से जवाबदेही तय होगी और नागरिकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

बक्सर जिले के शहरी नागरिकों को सीधी राहत

इस निर्णय से बक्सर जिले के बक्सर व डुमरांव नगर परिषद सहित चौसा, ब्रह्मपुर और इटाढ़ी नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इन इलाकों में जमीन और संपत्ति से जुड़े मामलों की संख्या अधिक है, जहां वंशावली की भूमिका अहम होती है। पहले दस्तावेज के अभाव में परिवारों को लंबे समय तक परेशान होना पड़ता था, अब उन्हें राहत की उम्मीद दिख रही है।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

यह फैसला राजस्व विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के समन्वय का परिणाम है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट हैकुनागरिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना। शहरी वंशावली को लेकर लिया गया यह निर्णय न सिर्फ प्रशासनिक सुधार का संकेत है, बल्कि आम लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा भी साबित होगा।

डिजिटल शिक्षा की नई उड़ान, बोधिका ई-पत्रिका के प्रवेशांक का भव्य विमोचन

- शिक्षा, नवाचार और संस्कार का संगम बनेगी बक्सर की पहली शैक्षिक ई-पत्रिका

केटी न्यूज/बक्सर

जिले में शिक्षा को डिजिटल मंच पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत शिक्षा विभाग की मासिक ई-पत्रिका ह्यबोधिकाह्न के प्रवेशांक का विधिवत विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासनिक सभागार में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी साहिला की गरिमामयी उपस्थिति में शिक्षा एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ई-पत्रिका का लोकार्पण किया।

विमोचन कार्यक्रम में अपर समाहर्ता अरुण कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप रंजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी चन्दन कुमार द्विवेदी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रजनीश उपाध्याय मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने ह्यबोधिकाह्न को जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सशक्त डिजिटल मंच बताया। जिलाधिकारी साहिला ने अपने संबोधन में कहा कि ह्यबोधिकाह्न ज्ञान, अनुभव और सूचना के आदान-प्रदान का आधुनिक माध्यम है, जो डिजिटल युग में शिक्षा को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह ई-पत्रिका शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप रंजन ने कहा कि ई-पत्रिका का संपादन रचनात्मक और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह विद्यालयों में हो रही शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं नवाचारी गतिविधियों का सजीव दस्तावेज है।

बक्सर की पहली डिजिटल शैक्षिक ई-पत्रिका

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी चन्दन कुमार द्विवेदी ने बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना, बक्सर के तत्वावधान में प्रकाशित ह्यबोधिकाह्न जनवरी 2026 में जारी की गई है और यह जिले की पहली डिजिटल शैक्षिक ई-पत्रिका है। इसका उद्देश्य शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर ज्ञान, नवाचार, संस्कार और सामाजिक चेतना से जोड़ना है।

विविध विषयों से सुसज्जित प्रवेशांक

प्रवेशांक में जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रेरणादायी संदेश, संपादकीय लेख सहित ह्यशिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में टी.एल.एम. की भूमिकाह्न, ह्यविद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा का महत्वह्न, योग स्तंभ ह्यकरें योग, रहें निरोगह्न, विज्ञान प्रदर्शनी-2025, ह्यसिविक सेंसह्न, ह्यसतरंगी दुनिया के अनोखे रंगह्न, ह्यएक दुनिया यह भी रू केस स्टडीह्न, ह्यइम्तहान की दस्तकह्न, ह्यसृजन के पंखह्न, विहंगम और विशेष स्तंभ मैं बक्सर हूँ जैसे रोचक व ज्ञानवर्धक विषय शामिल हैं।

तकनीकी रूप से सशक्त प्रस्तुति

क्यूआर-कोड आधारित सरल पहुंच, इंडेक्स-लिंक्ड कंटेंट, यूजर-फ्रेंडली नेविगेशन, आकर्षक ग्राफिक्स और विद्यालयीय गतिविधियों की वास्तविक तस्वीरों से सुसज्जित ह्यबोधिकाह्न पाठकों को सहज और प्रभावी डिजिटल पठन अनुभव प्रदान करती है।इस अवसर पर संपादन मंडल से जुड़े डॉ. नवनीत कुमार सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, रामभजन राम, विमल कुमार सिंह, मो. इमाम अली अंसारी, डॉ. मृत्युंजय राय, सुगंधा कुमारी, मोनिका कुमारी, विकास कुमार, सुभाष चौहान, राजेश कुमार राय, रवि शंकर गुप्ता, रवि प्रकाश, अजय कुमार सहित कई शिक्षक-कर्मी उपस्थित रहे।

Mob: 9122226720
कुमार आर्थोपेडिक्स क्लिनिक
सुमित्रा महिला कॉलेज से पूरब, बेलवानी मोड़, डुमराँव
डा. बिरेन्द्र कुमार
आर्थोपेडिक सर्जन
हड्डी, नस, गठिया रोग विशेषज्ञ
डा. एस.के. अम्बष्ठ
M.B.B.S (MKCC, ODISHA)
MD (Derma & Cosmetology),
KMC Manipal (Gold Medalist)
चर्म रोग, कुष्ट रोग, गुप्त रोग, सौंदर्य विशेषज्ञ
प्रत्येक मंगलवार
डा. अरूण कुमार
जेनरल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन
(M.B.B.S, D.NB. (New Delhi)
पेट रोग विशेषज्ञ
प्रत्येक गुरूवार

गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने की तैयारी तेज, डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

■ **सजावट, साफ-सफाई, झांकी व परेड को लेकर अधिकारियों को मिले स्पष्ट निर्देश**

केटी न्यूज/बक्सर

आगामी 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य, अनुशासित एवं यादगार बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह की तैयारियों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का पर्व है, ऐसे में इसकी तैयारी में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरे शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने, प्रमुख सड़कों, चौक-चौराहों तथा सरकारी भवनों को सुसज्जित करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शहर के सभी बिजली के खंभों पर तिरंगा लाइट एवं रंगीन बल्बों से आकर्षक सजावट सुनिश्चित कराई जाए।

बैठक में जिले के विभिन्न गणमान्य महानुभावों के प्रतिमा स्थलों की साफ-सफाई, रंग-रोगन तथा सौंदर्यीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। जिन प्रतिमा स्थलों एवं पार्कों में टाइल्स टूटे हुए हैं, उन्हें अविलंब बदलने का निर्देश दिया गया, ताकि शहर की छवि और सौंदर्य में कोई कमी न रहे।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तावित झांकी प्रदर्शन को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को दर्शाने वाली थीम आधारित झांकी का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर समर्पित करें, ताकि समय रहते चयन एवं तैयारी की जा सके।

परेड को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सार्जेंट मेजर को निर्देश दिया कि परेड टुकड़ियों का चयन कर ससमय अभ्यास प्रारंभ कराया जाए, जिससे मुख्य समारोह के दिन परेड का प्रदर्शन अनुशासित एवं प्रभावशाली हो।

मुख्य समारोह स्थल किला मैदान एवं समाहरणालय परिसर में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का दायित्व नजारत उप समाहर्ता एवं संबंधित पदाधिकारियों को सौंपा गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

पैक्स की तिजोरी खाली, जमाकर्ताओं की उम्मीदें छलनी, नया भोजपुर में 2 करोड़ के गबन ने खोली सहकारिता तंत्र की पोल

नया भोजपुर पैक्स बैंक घोटाला : सामूहिक आवेदन पर 2 करोड़ से अधिक गबन का दर्ज हुआ एफआईआर, जांच तेज

■ **आरडी-एफडी के नाम पर भरोसे की लूट, बैंक पर ताला, एजेंट फरार, सामूहिक शिकायत के बाद पुलिस व सहकारिता विभाग हरकत में**

केटी न्यूज/डुमरांव

नया भोजपुर के पैक्स बैंक घोटाले मामले में पीड़ितों के सामूहिक आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। कुल 32 पीड़ितों द्वारा पुलिस को दिए आवेदन में पैक्स बैंक पर दो करोड़ से अधिक की राशि गबन का आरोप लगाया गया है। बता दें कि नया भोजपुर की भोजपुर जदीद नया भोजपुर थाने का रुख किया, तो यह साफ हो गया कि मामला अब प्रबंधन की लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित आर्थिक घोटाले की शक्ल ले चुका है।

भरोसे का बैंक, गबन का अड्डा

पीड़ितों का आरोप है कि भोजपुर जदीद पैक्स में बचत खाता, आरडी और एफडी के नाम पर वर्षों से आम लोगों से पैसा जमा कराया गया। सब्जी विक्रेता, ठेला लगाने वाले, छोटे दुकानदार और ग्रामीण मजदूर, जिनके लिए हजार-बीस हजार की बचत भी जीवन का सहारा होती है। उन्होंने इस पैक्स को अपना बैंक माना, लेकिन 2023 से जैसे ही जमा राशि की परिपक्वता आई, भुगतान के बजाय केवल तारीखें मिलती रहीं। कुछ महीनों तक ह्लआज-कलह्व, ह्लअगले हफ्तेह्व का खेल चलता रहा, फिर एक दिन बैंक पर ताला लटक गया। न कर्मचारी, न प्रबंधक सिर्फ सन्नाटा। यहीं से खाताधारकों को यह एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ बड़ा खेल हो चुका है।

पैक्स अब केवल एक बैंक नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के टूटे भरोसे की कहानी बन चुकी है। वर्षों तक अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित समझकर जिस पैक्स में जमा कराया गया, वही आज कथित रूप से करीब दो करोड़ रुपये के गबन का केंद्र बन गया है। बुधवार को जब पीड़ित खाताधारकों ने सामूहिक रूप से

चार नामजद, सामूहिक शिकायत

शिकायतकताओं की अगुवाई कर रहे विकास कुमार ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन ने सुनियोजित तरीके से जमाकताओं की राशि हड़प ली। आवेदन में चार लोगों को नामजद करते हुए कहा गया है कि खाताधारकों के पासबुक और दस्तावेज भी ह्लनिकासी की प्रक्रियाह्व के बहाने जमा करा लिए गए, ताकि भविष्य में कोई ठोस दावा न किया जा सके। पीड़ितों का दावा है कि कुल जमा राशि करीब दो करोड़ रुपये के आसपास है। जब वे बैंक संचालकों के घर जाकर अपनी रकम मांगते हैं, तो कथित रूप से बदसलूकी की जाती है और उन्हें भगा दिया जाता है।

एजेंटों का नेटवर्क और छोटे कारोबारियों की लूट

इस घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू एजेंटों की भूमिका है। आरोप है कि एजेंटों के माध्यम से नया भोजपुर सब्जी मंडी और आसपास के इलाकों में छोटे व्यापारियों से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये जमा कराए गए। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद एक भी रुपया वापस नहीं किया गया। अब स्थिति यह है कि संबंधित एजेंट फोन उठाना बंद कर चुका है। यह सवाल भी उठ रहा है कि पैक्स जैसी सहकारी संस्था में एजेंटों के जरिये इतनी बड़ी राशि कैसे जमा कराई गई और इसकी निगरानी किसने की।

पहले भी दबा था मामला

पीड़ितों का कहना है कि 2025 में भी यह मामला सामने आया था। उस समय बैंक संचालकों ने कुछ चुनिंदा लोगों का पैसा लौटा दिया, जिससे बाकी जमाकताओं को उम्मीद जगी कि सबका पैसा मिल जाएगा। इसी भरोसे में तब एफआईआर नहीं कराई गई। लेकिन आज वही भरोसा सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है।

सहकारिता विभाग और पुलिस हरकत में

मामले की गंभीरता को देखते हुए सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, पटना प्रमंडल ने भी जिला सहकारिता पदाधिकारी को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर, नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच की जाएगी। एसपी शुभम आर्य के समक्ष भी पीड़ितों ने अपनी पीड़ा रखी है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी।

सिस्टम पर बड़ा सवाल

यह मामला सिर्फ एक पैक्स या एक गांव का नहीं है। यह सहकारिता तंत्र की निगरानी व्यवस्था, ऑडिट प्रणाली और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि समय रहते जांच और सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह घोटाला आने वाले दिनों में और बड़े संकट का रूप ले सकता है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासनिक सक्रियता से पीड़ितों में उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल वही है, क्या दोषियों तक कानून पहुंचेगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। नया भोजपुर के सैकड़ों परिवार आज इसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

छह पंचायतों का कन्या विवाह मंडप योजना के लिये हुआ चयन

केटी न्यूज/डुमरांव

कन्या विवाह मंडप योजना के तहत छह पंचायतों में भवन बनाने की मंजूरी मिल चूकी है। विवाह मंडप बनाने के लिये 50 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने के साथ ही राशि भी आवंटित हो चुकी है। इसकी जानकारी देते हुए पंचायती राज पदाधिकारी रोहणी कुमारी ने बताया कि चयननित पंचायतों में कुशलपुर, कनझरूआ, कोरानसराय मठिला, नुआंव व कसियां हैं। अन्य आठ पंचायतों के लिये जमीन को चयनित कर राशि आवंटित करने के लिये विभाग को भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। विदित हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह के लिये कराये पर भवन

लेना पड़ता था। किराए के भवन ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधाओं नहीं मिल पाती थी, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमीर लोग शहर में आकर बड़े-बड़े मैरेज हॉल और होटेल को बुक कराते हुए अपने कार्यक्रम को करते हैं। वहीं गरीब परिवार के लोग इतनी राशि खर्च नहीं कर पाते थे, जिससे गांव में ही किराये पर घर लेकर कार्यक्रम कराने पर मजबूर होते हैं। वहीं सरकार के द्वारा हर पंचायत में विवाह मंडप भवन जो 50 लाख खर्च कर बनाया जाएगा, उसमे सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाने की जैसे ग्रामीणों को मिली सभी ने खुशी जाहिर की।

ब्रह्मपुर में बिजली चोरी पर छापा, जांच दल से धक्का-मुक्की, धमकी और मोबाइल छीनने का आरोप

केटी न्यूज/ब्रह्मपुर

बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हंगामा सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने गई बिजली विभाग की जांच टीम पर न केवल जांच में बाधा डालने, बल्कि धमकी, गाली-गलौज और सरकारी साक्ष्य नष्ट करने की गंभीर कोशिश का आरोप लगा है। इस मामले में विभाग ने विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

कनीय विद्युत अभियंता के नेतृत्व में गठित जांच दल जब पांडेयपुर महुआर पंचायत के पांडेयपुर स्थित अनिल पांडेय के परिसर में पहुंचा, तो वहां उपभोक्ता संख्या

218510108798 के नाम दर्ज मीटर संख्या I7122416 से अवैध तरीके से बिजली उपयोग किए जाने के साक्ष्य मिले। आरोप है कि मीटर के इनपुट सर्विस तार से पहले अवैध तरीके से कनेक्शन काटकर अतिरिक्त तार जोड़ा गया था, जिससे मीटर को बायपास कर घरेलू उपकरणों का संचालन किया जा रहा था। इस कृत्य से विभाग को लगभग 80,924 रुपये की राजस्व क्षति होने का आकलन किया गया है। जांच में कुल 2.271 किलोवाट का अवैध भार उपयोग पाया गया।

जांच के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब अभियुक्त और उसके 4-5 सहयोगियों ने टीम के साथ धक्का-मुक्की की, गाली-गलौज की और कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। आरोप है कि जांच के दौरान वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड कर रहे अभियंता का मोबाइल फोन छीन लिया गया और साक्ष्य डिलीट करने की कोशिश की गई। हंगामे के कारण तत्काल बिजली कनेक्शन विच्छेद और मीटर जब्ती की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।

घटना की सूचना पर ब्रह्मपुर थाने की गश्ती पार्टी मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में दोबारा कार्रवाई की कोशिश की गई, लेकिन तब भी विरोध के चलते केवल पोल से आंशिक तार विच्छेदन ही संभव हो पाया। इस मामले में ब्रह्मपुर जेई अमित कुमार राय के बयान पर ब्रह्मपुर थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने, साक्ष्य से छेड़छाड़ और बिजली चोरी का संगठित प्रयास बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मामले ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान में बढ़ते विरोध और कानून-व्यवस्था की चुनौती को उजागर कर दिया है। अब निगाहें पुलिस कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज होने पर टिकी हैं।

कड़ाके की ठंड में पशुधन की ढाल बनी मोबाइल वेटेनरी एंबुलेंस

■ **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल, पशुपालकों के लिए उम्मीद की किरण**

केटी न्यूज/चौसा

लगातार गिरते तापमान और शीतलहर के बीच जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त है, वहीं पशुधन पर इसका असर कहीं अधिक गंभीर रूप से सामने आ रहा है। प्रखंड क्षेत्र और आसपास के गांवों में कड़ाके की ठंड ने पशुओं की सेहत पर सीधा हमला बोला है। गाय, भैंस, बकरी और बछड़ों में सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर नवजात और वृद्ध पशु हाइपोथर्मिया, निमोनिया, कमजोरी और भूख न लगने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है।

पशुपालकों के लिए संजीवनी बनी सेवा

ऐसे हालात में मोबाइल वेटेनरी एंबुलेंस सेवा ग्रामीण पशुपालकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं साबित हो रही है। ठंड और कोहरे की परवाह किए बिना मोबाइल वेटेनरी टीम गांव-गांव पहुंचकर बीमार पशुओं का त्वरित और निःशुल्क इलाज कर रही है। पशु चिकित्सक डॉ. अजय प्रकाश यादव के नेतृत्व में परावेट अमित सिंह और चालक शत्रुधन सिंह की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। यह टीम न केवल प्राथमिक उपचार बल्कि गंभीर मामलों में तुरंत दवा, इंजेक्शन और जरूरी परामर्श देकर पशुओं की जान बचाने में अहम भूमिका निभा रही है।

इलाज के साथ जागरूकता पर जोर

मोबाइल वेटेनरी एंबुलेंस की खास बात यह है कि इलाज के साथ-साथ पशुपालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। टीम किसानों को सलाह दे रही है कि पशुओं के आवास को ठंडी हवाओं से सुरक्षित रखें, सूखा और गर्म बिछावन दें, गुनगुना पानी पिलाएं और संतुलित आहार सुनिश्चित करें। साथ ही समय पर टीकाकरण और नवजात पशुओं की विशेष देखभाल पर भी जोर दिया जा रहा है।

गांव-गांव पहुंची राहत

बुधवार को सरेंजा, कठतर, राजापुर और बनारपुर गांवों में मोबाइल वेटेनरी एंबुलेंस पहुंची, जहां दर्जनों पशुओं का उपचार किया गया। ग्रामीण पशुपालकों सुरेश, जीवन कुमार और राम सिंह ने बताया कि इस सेवा के कारण कई पशुओं की जान बच सकी है। उनका कहना है कि अगर समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचते, तो ठंड के कारण भारी नुकसान हो सकता था।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को सहारा

पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में मोबाइल वेटेनरी एंबुलेंस न केवल पशुओं की रक्षा कर रही है, बल्कि किसानों की आजीविका को भी सुरक्षित रखने में अहम योगदान दे रही है। कड़ाके की ठंड में यह सेवा ग्रामीण इलाकों के लिए भरोसे और राहत का बड़ा माध्यम बनकर उभरी है।

नाथ बाबा मंदिर से चंदन चोरी में साजिश की बू, सीआईडी जांच की उठी मांग

केटी न्यूज/बक्सर

बक्सर के नाथ बाबा मंदिर परिसर से चंदन के दो पेड़ों की चोरी का मामला अब रहस्यमय और संदेहास्पद बनता जा रहा है। 22 दिसंबर की रात सदर एसडीओ आवास से सटे नाथ बाबा मंदिर में चोरों ने न केवल घुसपैठ की, बल्कि भारी-भरकम चंदन के दो पेड़ काटकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस सनसनीखेज चोरी के आठ दिन बाद मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित यमुना घाट से 48 घंटे के अंतराल पर दोनों चंदन पेड़ों की लकड़ियां बरामद हुईं, लेकिन चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि चोर सदर एसडीओ आवास परिसर में रखी सीढ़ी और रस्सी का इस्तेमाल कर

मंदिर में दाखिल हुए और उसी रास्ते से चंदन के पेड़ों को लेकर बाहर भी निकले। एसडीओ आवास की सुरक्षा में तैनात रात्रि प्रहरी और सुरक्षा गार्ड की भूमिका को लेकर भी संदेह गहराता जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी की रात सदर एसडीओ अविनाश कुमार आवास पर मौजूद नहीं थे, वे बक्सर से बाहर थे। वहीं, मंदिर के महंत भी उस रात अनुपस्थित थे। सवाल यह उठता है कि चोरों को इन दोनों की गैरमौजूदगी की सटीक जानकारी कैसे थी। इसके अलावा नाथ बाबा मंदिर में चंदन के पेड़ होने की जानकारी आम लोगों या नियमित भक्तों को भी नहीं थी, फिर चोरों तक यह सूचना कैसे पहुंची। एक ही घाट से 48 घंटे के अंतराल पर चंदन की लकड़ियों की बरामदगी ने पुलिस जांच पर और भी प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। चोरी की जांच में लगी पुलिस आखिर क्या कर रही थी कि चोर इतनी आसानी से लकड़ियां घाट पर छोड़कर चले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। मामले की गंभीरता और संभावित अंदरूनी मिलीभगत को देखते हुए अब स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे प्रकरण की ब्क जांच कराने की मांग तेज कर दी है। लोगों का कहना है कि निष्पक्ष और गहन जांच के बिना इस रहस्य से पर्दा

1.88 करोड़ घरों में पहुंचाया जा रहा शुद्ध पेयजल : मंत्री

- विभाग के नवनियुक्त 107 सहायक अभियंताओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे लोक स्वाथ्य अभियंत्रण मंत्री
- कहा, पेयजल की गुणवत्ता और सुविधाजनक आपूर्ति सुनिश्चित करें विभाग के अभियंतागण

एजेंसी/पटना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि उनका विभाग राज्य के कुल 1.88 करोड़ घरों में कुल 1.20 लाख योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रहा है। हमारे समक्ष आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता और उसकी सुविधाजनक आपूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौती है। उनका विभाग राज्य में लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने वाला केवल अभियांत्रिक नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों के बंधनों से बंधा विभाग भी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बुधवार को राजधानी के बापू टावर स्थित सभागार में विभाग में नवनियुक्त कुल 107 सहायक अभियंताओं के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इन अभियंताओं में 35 प्रतिशत से अधिक महिला अभियंता भी शामिल हैं। नवनियुक्त अभियंताओं को संबोधित करते हुए तथा बाद में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ने कहा कि ह्लहर घर नल का जलह्व योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे पूरे राज्य में सफलता के साथ संचालन करना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, अभियंता प्रमुख नित्यानंद और अपर सचिव अरविंद कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। विभागीय मंत्री ने नवनियुक्त सहायक अभियंताओं से कहा कि उनके विभाग द्वारा अब हर साल श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों, अभियंताओं और कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अपने कार्य में लापरवाही बरतने वालों के लिए भी विभाग ने दंड का प्रावधान किया है। मेरी मान्यता है कि विभाग को अपने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी-अभियंता को दण्डित करने की जरुरत न पड़े। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ने कहा कि हमारा विभाग कुल 30 कॉल सेंटरों के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता और सुविधापूर्ण आपूर्ति के सम्बंध में आमलोगों की शिकायतें दर्ज करता है और उनका एक तय समय-सीमा में निवारण करता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दे रखा है कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर बिजली विपत्रों और संवेदकों के बकाए का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सभी नवनियुक्त 107 अभियंताओं का अपने विभाग में स्वागत करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब विभाग में नियुक्ति के बाद अभियंताओं के लिए गयाजी के बिपार्ड में दो महीने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि बिना पूवार्नुमति कोई भी अभियंता अपना मुक्यालय न छोड़ें।

तीन माह में सरकार की नई पहल से हर बिहारी होगा गौरवांवित : उपमुख्यमंत्री

- उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने किया कम्पैडियम का लोकार्पण

एजेंसी/पटना

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिंहा ने कहा कि जिलों में आयोजित किये जा रहे राजस्व विभाग के जन संवाद कार्यक्रम से लोगों की विश्वास एवं अपेक्षाएं बढ़ी है। इस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। तीन माह में सरकार की नई पहल से हर बिहारी गौरवान्वित होगा। इसके लिए राजस्व विभाग सुखद, स्वस्थ वातावरण का माहौल बनाने में जुटा है। उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को पुराना सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। इसके पूर्व उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्ष 2003 से 2023 तक जारी सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं नियमों को एक सुव्यवस्थित रूप में संग्रहित कर चार खंडों में तैयार किये गए विभागीय कम्पैडियम (परिपत्र संग्रह) का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत लागू राजस्व नियमो अधिनियमों तथा परिपत्रों की अद्यतन और प्रामाणिक जानकारी राज्य के सभी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तक सरलता से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के नियमों और परिपत्रों को एक स्थान पर संकलित करने से विभागीय कार्यप्रणाली में एकरूपता आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी। कम्पेंडियम की उपलब्धता से अधिकारियों को नियमसंगत तरीके से कार्य करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। कम्पेडियम को चार भागों में इस प्रकार तैयार किया गया है कि परिपत्रों एवं प्रावधानों की खोज आसान हो सके।

इसके भाग 1 में भू-अभिलेख एवं परिमाप तथा चकबंदी से संबंधित संग्रह है। भाग 2 में भू-अर्जन तथा भाग-3 में (a) में खासमहाल, भू-हस्तान्तरण, भूमि बन्दोबस्ती, लोक भूमि अतिक्रमण, (b) में सैरात एवं फेरीघाट बन्दोबस्ती, राजस्व संग्रहण, भू-लगान, सेस, मेला प्राधिकार, (c) में वासभूमि बन्दोबस्ती (बी०पी०पी०एच०टी० एक्ट), बेदखली (दखल देहानी), अभियान बसेरा, (d) में भू. हदबंदी (सिलिग), भूदान और (e) में काश्तकारी, बटाईदारी (बी० टी० एक्ट) कृषि भूमि सम्परिवर्तन से संबंधित संग्रह है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह संकलन विभागीय नियमों को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से राज्यभर के पदाधिकारी अद्यतन प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर बेहतर ढंग से जनहित से जुड़े कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। विभाग को विश्वास है कि इन चारों कम्पेंडियम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को भी त्वरित एवं सटीक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में महत्वपूर्ण कार्य पीएम किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फॉर्मर आईडी बनाने का कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय से भी 15 अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 7 से 10 प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं, प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू किये गए जनसंवाद कार्यक्रम से जन सहयोग बढ़ा है वह अद्वितीय है। अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप में तीन हल्का कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार किये गए हैं, जिसमें वैशाली, शिवहर और पटना का एक हल्का कर्मचारी शामिल है। उन्होंने कहा कि जन संवाद का असर जनता में हुआ है। तीन माह में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस के मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसे 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी लोगों को सम्मान के साथ न्याय मिले यह नई सरकार का मूल उद्देश्य है। इस मौके पर सचिव गोपाल मीणा, विशेष सचिव अरूण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन होने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दो माह के अंदर कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में दाखिल-खारिज से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निष्पादन दर 75.30 फीसदी से बढ़ कर वर्तमान में 82 फीसदी हो गया है।

एसडीएम ने भारत स्काउट और गाइड रोहतास टीम को हरी झंडी दिखा किया रवाना

- छत्तीसगढ में प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर की 27 सदस्यीय टीम करेगी शिरकत

केटी न्यूज/रोहतास

बिक्रमगंजनई दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय के नेतृत्व में हो रहे प्रथम रोवर रेंजर जंबूरी के लिए भारत स्काउट एवं गाइड,रोहतास जिला के तत्वावधान में प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी में सहभागिता के लिए जिले की 27 सदस्यीय स्काउट गाइड टीम को जिला संगठन आयुक्त अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में एसडीएम प्रभात कुमार,प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार एवं प्राचार्या प्रमिला सिंह,डीएवी स्कूल सेमरा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जंबूरी 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक बुधली जो छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी, जिसमें देशभर के लगभग 15 हजार स्काउट-गाइड, रोवर एवं रेंजर भाग लेंगे। डीएवी स्कूल सेमरा बिक्रमगंज से बस के द्वारा आरा जंक्शन से साउथ बिहार एक्सप्रेस से दुर्ग छत्तीसगढ़ के लिए

रवाना होंगे। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रसेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ किया जाएगा। रोहतास की चयनित टीम में डी ए वी सेमरा बिक्रमगंज से गाइड में अंशी आर्या,सांवली सिंह, सोनाक्षी कुमारी, आरुषि कुमारी, सलोनी कुमारी, रियांशी कुमारी, श्रेष्ठा कुमारी, स्काउट में- अर्पित सिंह,चंदन पटेल, कुमार श्रेयस, विपुल कुमार,दिव्य प्रकाश, अभिषेक कुमार गुप्ता, अमन कुमार, निखिल प्रकाश, आशीष कुमार, सुधांशु राय, आयुष कुमार गिरी प्रकाश कुमार ध्रुव कुमार, इंटर विद्यालय गौशलडीह,सूर्यपुरा से खुशी कांजली सिंह, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोनहर से साहस कुमार,उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरैना से शिवम कुमार, रामदुलारी गंगा उच्च विद्यालय चेनारी से आर्यन राज भाग लेंगे इस मौके पर विद्यालय के स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन के साथ विभिन्न लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की सूचना, जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रियंका कुमारी, मुख्य जिला आयुक्त सह पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्य देव पासवान,के साथ संगठन के सभी लोगों को दी गई सभी पदाधिकारीयों ने इस कार्यक्रम की काफी सराहना किया और आगे भी बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

किसान रजिस्ट्री संयुक्त प्रयास से लक्ष्य पूर्ति को दी जायेगी सर्वोच्च प्राथमिकता : सीओ

केटी न्यूज/रोहतास

अंचलाधिकारी मधुसूदन चौरसिया ने किसानों से अपनी किसान आईडी को समय पर सत्यापित,सुरक्षित और अद्यतन कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि किसान आईडी सरकारी योजनाओं,अनुदान,फसल सहायता और अन्य लाभों से किसानों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। किसान आईडी के सत्यापन और संरक्षण की प्रक्रिया पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर लगातार जारी है। इसके लिए किसानों को अपने आधार कार्ड और भूमि से संबंधित रसीद जैसे लगान रसीद या राजस्व रसीद के साथ संबंधित पंचायत कर्मचारी, किसान सलाहकार और प्रखंड कर्मियों से संपर्क करना होगा। दूसरी तरफ उपलब्ध दस्तावेजों तहत अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसान आईडी के अभाव में कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त

करने में कठिनाई हो सकती है। इसी क्रम में किसान पंजीकरण कार्य की प्रगति को गति देने के उद्देश्य से अंचलाधिकारी मधुसूदन चौरसिया ने बुधवार को अंचल क्षेत्र में चल रहे किसान पंजीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संसाधनों की उपलब्धता, काउंटर व्यवस्था, कार्यप्रवाह और कर्मियों की भूमिका की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान, अंचलाधिकारी ने बताया कि किसान पंजीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जो किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने में सहायक है। उन्होंने पंचायत स्तर पर तैनात सभी कर्मियों को निर्देश दिया कि पंजीकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही, किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा। जबकि अंचलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि सभी कर्मी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत किसान पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। इसका उद्देश्य किसानों को योजनाओं का समय पर लाभदिलाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

जू में चप्पे-चप्पे पर लगेगा सीसीटीवी, मोबाइल देगा जानवरों-पौधों की जानकारी

- अब पटना जू का टिकट कटा सकेंगे ऑनलाइन, 15 दिन में शुरू होगी सुविधा
- फरवरी से गाइड के सहयोग से कर सकेंगे टूर, नया मोबाइल ऐप भी होगा लॉच

एजेंसी/पटना

राजधानी पटना में मौजूद संजय गांधी जैविक उद्यान (जू या चिड़ियाघर) में सुविधाएं और सुरक्षा दोनों बढ़ाई जाएंगी। चप्पे-चप्पे की चौकसी सीसीटीवी कैमरे से होगी। समेकित चौकसी और नियंत्रण के लिए एक विशेष कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा जू का अपना एक खास मोबाइल एप विकसित किया जा रहा है, जिसके फरवरी तक तैयार हो जाने की संभावना है। इसकी मदद से

यहां मौजूद सभी जानवरों और पौधों की जानकारी मिलेगी। एप की मदद से चिड़ियाघर घूमने का अलग ही अनुभव होगा। किसी भी पौधे या जानवर के नजदीक जाने पर इस एप पर संबंधित जीव-जंतु या पौधे की जानकारी खुद डिस्प्ले हो जाएगी। आगामी 15 दिनों में इसका टिकट ऑनलाइन माध्यम से भी खरीद सकते हैं। जू के आधुनिकीकरण और इसे नए कलेवर में प्रस्तुत करने को लेकर विस्तृत जानकारी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने दी। वे जू परिसर में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर आनंद किशोर ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू होने पर ऑफलाइन या काउंटर से टिकट बुकिंग की मौजूदा व्यवस्था बदस्तूर जारी रहेगी। इस वर्ष फरवरी से यहां टूर गाइड की सुविधा भी शुरू होगी, जिनकी मदद से बाहर से आने वाले कोई सैलानी जू के सैर का पूरी जानकारी के साथ आनंद ले सकते हैं। इसके लिए निर्धारित शुल्क तय रहेगा। हाल में मुख्यमंत्री ने जू भ्रमण के दौरान स्कूली बच्चों को यहां से जोड़ने पर जोर दिया था। इसके तहत यहां शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सेमिनार, सूचना प्रसार कार्यक्रम जैसे अन्य आयोजनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसे लेकर जू का वार्षिक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जू परिसर में 150 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है, जिसे एक आधुनिक कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। यहां से चिड़ियाघर के हर स्थान की समुचित तरीके से मॉनीटरिंग हो सकेगी। यहां से हर आने-जाने वाले के साथ ही जू के अंदर की सभी गतिविधियों पर चौबीस घंटे नजर रखी जा सकेगी। यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही एक अनोखा ट्री-टॉप वॉक-वे की शुरूआत की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एक सोविनियर शॉप का निर्माण भी कराया जा रहा है। लोगों से प्राप्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए यहां एक नर्सरी की स्थापना भी की जा रही है, जहां से किफायती दरों पर पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण पर्यटकीय सुविधाओं के विस्तार के तहत इसके परिसर में फूड कियोस्क लगाए जाएंगे। जू के दोनों प्रवेश द्वारों का नए तरीके से सौंदर्यीकरण कराने की योजना है। ताकि ये अधिक आकर्षित लगें। आगंतुकों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में शेड्स, दीवारों पर दोनों तरफ थ्री-डी पेंटिंग, जू वॉलेंटियर और जू-मित्र कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी। मछली घर और मेडिसिनल गार्डन को अधिक बेहतर और आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। सफाई कार्य में प्रदूषणमुक्त वाहनों का उपयोग होगा।

ठंड से बचाने के लिए डीडीसी और डीआरडीए ने असहायों में किया कंबल वितरण

केटी न्यूज/नवादा

रजौली कड़ाके की ठंड और बढ़ती कनकनी के बीच मानवता की सेवा का संकल्प लेते हुए रजौली नगर पंचायत कार्यालय में आपदा प्रबंधन की ओर से एक विशेष राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आईएएस अधिकारी सह उप विकास आयुक्त नीलिमा साहू ने स्वयं उपस्थित होकर लगभग सत्तर गरीब और असहाय लोगों के बीच गर्म कंबलों का वितरण किया।भीषण शीतलहर के इस दौर में प्रशासन की इस सक्रियता से समाज के वंचित तबके को बड़ी राहत मिली है।इस महत्वपूर्ण अवसर पर डीडीसी के साथ डीआरडीए निदेशक धीरज कुमार और डीपीओ विकेष कुमार की उपस्थिति ने

प्रशासनिक तत्परता को और मजबूती प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्तर पर कमान संभाल रहे प्रभारी नगर पंचायत सह अंचलाधिकारी गुफरान मजहरी और प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कराया।नगर पंचायत की स्वच्छता और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता पदाधिकारी राहुल कुमार समेत नगर पंचायत के तमाम कर्मचारी वहां मुस्तैद रहे, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक सहायता पहुंच सके।कंबल वितरण की इस कड़ी में अधिकारियों ने न केवल ठंड से राहत प्रदान की, बल्कि बुजुर्गों और निशक्तों से संवाद कर उनकी अन्य मूलभूत समस्याओं को भी समझा।

एक नजर

मीटर बाईपास बिजली चोरी से बाज नहीं आ रहें लोग लोग,दो पर केस दर्ज

बिक्रमगंज । अवैध बिजली चोरी के खिलाफ स्थानीय बिजली विभाग के अधिकारियों ने चलाया छापेमारी अभियान। जो अवैध चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभागीय टीम ने नगर परिषद क्षेत्र के अहमद नगर में छापेमारी कर दो उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली चोरी में दबोचा। इसके बाद विभाग ने आरोपी के खिलाफ स्थानीय बिक्रमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जुमार्ना लगाया है। इस संदर्भ में बिजली विभाग के कनीय विद्युत अभियंता नवदीप गोयल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। इस टीम में तकनिकी कर्मचारी व मानवबल शामिल थे। जिसे लेकर छापेमारी टीम ने मंगलवार को वार्ड 25 स्थित छापेमारी के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा मीटर से पहले सर्विस तार में कटिंग कर अवैध तरीके से तार जोड़कर तथा मीटर बाईपास कर बिजली की चोरी की जा रही थी। जिसको लेकर अख्तरी खातून पति अजीमुल्लाह खान पर 35328 रुपए और अनवर खान, पिता तौहीद खान पर 14377 रुपये की राजस्व की क्षति लगायी गयी है। दोनों ही मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने को आवेदन सौंपा गया है। छापेमारी दल में लाइनमैन अविनाश कुमार, मानवबल सोनू कुमार सिंह, महेश सिंह, शिवनाथ सिंह आदि मौजूद थें। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बिक्रमगंज मे दिसंबर माह मे 59 लोगों पर विद्युत ऊर्जा चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है जिसमें कुल जुमार्ने के राशि 22.87 अधिरोपित है।

एक माह के अंदर लंबित मामलों का करें निष्पादन : एसीएस

पटना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में बुधवार को सभी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ निगरानी संबंधी मामलों की समीक्षा की गयी। बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में निगरानी विभाग के स्तर से सभी विभागों को प्रेषित ऑनलाइन परिवादों के जाँच प्रतिवेदन की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि तीन हजार से अधिक परिवाद सभी विभागों को प्रेषित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक मामले शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग से संबंधित हैं । अपर मुख्य सचिव ने निदेश दिए कि जिन विभागों में परिवादों से संबंधित कार्रवाई लंबित हैं, उनका शीघ्र निष्पादन किया जाय। विदित है कि विगत वर्ष ही निगरानी के परिवादों हेतु ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की गयी, जिससे बेहतर ट्रैकनिज्मि विकसित हुई तथा उनके निष्पादन में काफी सहूलियत मिली है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार द्वारा जानकारी दी गयी कि ब्यूरो के स्तर से भी निगरानी संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। विगत वर्ष कुल 122 कांड दर्ज किए गए, जिनमें से 102 मामले ट्रैप से संबंधित थे । सभी विभागों के अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की गयी, जिसमें कुल 53 मामले लंबित पाए गए। इसमें सर्वाधिक लंबित मामले जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के हैं । इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग के स्तर से सभी विभागों में मुख्य निगरानी पदाधिकारी द्वारा मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाय । बैठक में बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के उप महानिरीक्षक श्री नवीन चन्द्र झा, विशेष निगरानी इकाई के उप महानिरीक्षक श्री विकास कुमार, अपर सचिव श्री रामाशंकर, तकनीकी परीक्षक कोषांग के अभियन्ता प्रमुख श्री शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (विधि) श्रीमती अंजू सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे।

राज्य में जुगाड़ गाड़ियों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

पटना। राज्य में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध संचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगने जा रहा है। परिवहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसके संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। इसे कड़ाई से लागू करने के लिए सभी डीटीओ को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रिय व राज्य राजमार्ग के साथ शहरों में चलने वाली जुगाड़ वाहनों व चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करेंगे। ये जुगाड़ गाड़ियां मुख्य रूप से डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल हैंडल और माल ढोने वाले रिक्शा-ठेले की बॉडी को जोड़कर बनाई जाती हैं। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के वाहन मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 और बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 की किसी भी धारा या नियम में वर्णित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसियों से ऐसे वाहनों के प्रोटोटाइप की मंजूरी का प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं होता। इसके नतीजतन, इन वाहनों का पंजीकरण, परमिट, बीमा, फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण-पत्र आदि नहीं हो पाता। साथ ही ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्ति या वाहन मालिक को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी नहीं मिल सकता। इनके संचालन से विभागीय नियमों की खुलेआम अवहेलना होती है और ट्रैफिक भी बाधित होता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है।

बिहार को बड़ी सौगात : 5 स्टेट हाइवे के निर्माण के लिए 2900 करोड़ की मिली मंजूरी

एजेंसी। पटना

बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में जल्द ही 5 प्रमुख स्टेट हाइवे के निर्माण का काम जोर-शोर से शुरू होने वाला है। इन परियोजनाओं के लिए एशियन विकास बैंक (ADB) की ओर से लगभग 2900 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी मिलते ही बिहार राज्य पथ विकास निगम (Bihar State Road Development Corporation) ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य पथ विकास निगम ने हाल ही में एडीबी को पीबीई (Price Bid Evalution) रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एडीबी ने इन पांचों स्टेट हाइवे परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। एडीबी की मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार को चरणबद्ध तरीके से फंड उपलब्ध कराया जाएगा और उसी के अनुरूप निर्माण कार्य भी फेज वाइज पूरा किया जाएगा। इन पांच स्टेट हाइवे परियोजनाओं के तहत लगभग 225 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। इनमें से कई सड़कें पहले टू-लेन की थीं, जिन्हें अब चौड़ा कर सिक्स लेन बनाया जाएगा। इससे न केवल ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि यात्रा भी अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी। इन परियोजनाओं के लिए पहले ही डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार कर ली गई थी। इसके साथ-साथ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अब एडीबी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने इन सभी स्टेट हाइवे परियोजनाओं को दो साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो, इसके लिए निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। परियोजनाओं की निगरानी भी नियमित रूप से की जाएगी ताकि गुणवत्ता और समयसीमा दोनों का पालन हो सके। इन पांच स्टेट हाइवे के निर्माण से बिहार के 8 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा।

बिहार में जिन 5 स्टेट हाइवे का निर्माण किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं

सारण और सीवान जिला : छपरा, मांझी, दरौली, गुठनी
मुंगेर और बांका जिला : असरगंज, शंभूगंज, इंग्लिश मोड़, पुनसिया धोरैया
मुजफ्फरपुर जिला : हथौड़ी, अतरार, बभनगामा, औराई
गयाजी जिला : बनगंगा, जेठियन, गहलौर, भिंडस
भोजपुर जिला : आरा, एकौना, खैरा, सहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया सख्त आदेश

सप्ताह में दो दिन पंचायत से लेकर प्रमंडल तक सभी अधिकारी सुनेंगे आपकी बात

एजेंसी। पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरूआत करने का एलान किया है। सीएम ने पंचायत से लेकर प्रमंडल तक के अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि आपलोग सप्ताह में दो दिन अब जनता दरबार लगाएंगे और उसमें आम लोगों की समस्या सुनेंगे और उसका त्वरित गति से निष्पादन भी करेंगे। सीएम ने इसको लेकर सप्ताह में यह दो दिन कौन से होंगे यह भी तय कर दिया है। सीएम ने इस जनता दरबार में सप्ताह में कार्यदिवस के पहले दिन और उसके बाद कार्यदिवस के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को जनता दरबार लगाने का आदेश दिया है। इसकी शुरूआत 19 जनवरी से होगी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मिडिया पोस्ट एक्स के जरिए पोस्ट कर यह जानकारी दी है कि - प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल/कार्यालय कक्ष में मिलेंगे"। सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि - आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हमलोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय सबका सम्मान-जीवन आसान का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हमलोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसे देखते हुए अब राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं- प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल/कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी। आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसके लागू होने से आमजनों को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 10 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं।

एक नजर

बिजली कनेक्शन के नाम पर घूसखोरी, मुजफ्फरपुर में 5 हजार रुपये रंगेहाथ घूस लेते जेई सहित 3 कर्मी गिरफ्तार

पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में विशेष निगरानी इकाई, पटना की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जे.ई) सहित 3 लोगों को 5000 घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आए दिन घूसखोर पकड़े जा रहे हैं, इसके बावजूद ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज फिर निगरानी के हत्थे तीन घूसखोर चढ़ गये हैं। यह कार्रवाई मोहम्मद जाहिद, पिता मोहम्मद जहाँगीर, ग्राम आशापट्टी परसौनी के लिखित शिकायत के आधार पर की गई। जाहिद ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने के एवज में विद्युत विभाग, साहेबगंज के जे.ई. श्री गौतम कुमार, निशांत (M.R.C.) और मुनचुन राय (लाईनमैन) द्वारा कुल 12 हजार रुपए रिश्वत की माँग की जा रही थी। आरोप है कि रिश्वत न देने पर कनेक्शन नहीं लगाने और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी भी दी गई थी। पीड़ित की शिकायत के बाद मामले का सत्यापन किया गया। निशांत और मुनचुन राय ने कथित तौर पर दबाव डालकर शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये ले लिए थे और बाकी 7 हजार रुपये आज देने को कही गयी थी। 07 जनवरी को विशेष निगरानी इकाई की टीम ने मोहम्मद जाहिद की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा X के तहत मामला दर्ज किया गया है। विशेष निगरानी इकाई द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और अब सभी आरोपियों को निगरानी न्यायालय, पटना में पेश किया जाएगा।

10 हजार के इनामी फरार भू-माफिया हरि सिंह पटना से गिरफ्तार, एसपी ने घोषित किया था इनाम

मोतिहारी। पुलिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर मुहिम चला रही है. कई फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के द्वारा इनाम की घोषणा की गई है. मोतिहारी नगर निगम के वार्ड पार्षद पति हरि सिंह के खिलाफ भी एसपी ने 10 हजार रू इनाम की घोषणा की थी. पुलिस वार्ड पार्षद पति की गिरफ्तारी को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी की. मोतिहारी पुलिस ने फरार भू माफिया हरि सिंह को आज बुधवार को पटना से गिरफ्तार कर लिया है. 10 हजार रू का इनामी हरि सिंह को मोतिहारी पुलिस ने पुत्र के साथ गिरफ्तार किया है. पटना पुलिस की मदद से छतौनी थाना की पुलिस ने आरोपी हरि सिंह को गिरफ्तार किया है. .हरि सिंह पर भू माफियागिरी का आरोप है. इसके बाद एसपी ने दस हजार के ईनाम की घोषणा की थी. बता दें, मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक ने 31 दिसंबर 2025 को नगर निगम के वार्ड पार्षद के पति हरि सिंह पर 10 हजार रू का इनाम घोषित किया था. पुलिस अधीक्षक ने शहर के छोटा बरियारपुर के वार्ड 39 के पार्षद पति हरि सिंह उर्फ हरिशंकर सिंह पर 10000 रुपए ईनाम की घोषणा की थी. छतौनी कांड संख्या 723/25 में हरि सिंह फरार थे।

पूर्णिया पुलिस का बड़ा एक्शन: बाइक चोर गिरोह का खुलासा, छह बदमाश गिरफ्तार

पूर्णिया। पूर्णिया पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक स्वीटी सेहरावत ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पूर्णिया एसपी स्वीटी सेहरावत ने बताया कि चंपानगर थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी के बाद बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी की गई बाइकों को गिरोह के सदस्यों द्वारा संचालित गैराज में ले जाकर उनका चेचिस और इंजन नंबर घिस दिया जाता था, जिसके बाद बाइक को पार्ट्स में काटकर या कस्टमर तलाश कर बेच दिया जाता था।

पटना के तमाम ज्वेलरी शॉप में लग गया नो एंट्री का नोटिस यह नियम लागू करने वाला बिहार बना देश का पहला राज्य

एजेंसी। पटना

चेहरा ढककर सोने-चांदी की दुकान में गहना खरीदने यदि आप जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि 8 जनवरी से नया नियम लागू होने जा रहा है। मास्क, नकाब, बुर्का, हेलमेट, मफलर, हिजाब चेहरे पर लगाकर यदि कोई ज्वेलरी शॉप में सोना-चांदी के आभूषण खरीदने जाता है, तो सबसे पहले उनकी एंट्री दुकान में नहीं दी जाएगी। मास्क और नकाब पहनकर दुकान में जाने पर आभूषण नहीं दिया जाएगा। चेहरा ढका रहा तो आप गहना नहीं खरीद सकेंगे। लूट और डकैती की की घटनाओं को देखते हुए अक्क्खत्र्क्ष्ट ने यह फैसला लिया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों ने अपने-अपने दुकान के सामने यह नोटिस लगा दिया है। पटना के लगभग सभी सोने-चांदी की दुकान के आगे पोस्टर चिपका दिया गया है। उसमें यह लिखा गया है कि सूचना..कृपया मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। व्यवस्थापक.. बता दें कि सिक्योरिटी के उद्धेश्य से यह फैसला लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में हिजाब वाली औरतें अब गहना नहीं खरीद सकेंगी। जो व्यक्ति अपना चेहरा ढककर दुकान में जाने की कोशिश करेंगे उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। ज्वेलरी शॉप में एंट्री से जुड़ा यह नियम 8 जनवरी से लागू होगा। यह निर्णय राज्य भर में एक साथ लागू होगा और इसका असर हर छोटे-बड़े शहर की ज्वेलरी दुकानों पर दिखाई देगा। जिसके तहत ज्वेलरी खरीदते समय चेहरा दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर बिहार के ज्वेलरी व्यापारियों ने इस नियम को लागू करने का निर्णय लिया है।

जस्टिस संगम कुमार साहू बने पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश

एजेंसी। पटना

पटना उच्च न्यायालय में बुधवार को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब जस्टिस संगम कुमार साहू ने न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथ्री के सेवानिवृत्त होने के बाद 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जस्टिस साहू की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले महीने शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में जस्टिस साहू के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की। इससे पहले पटना हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सुधीर सिंह जिम्मेदारी निभा रहे थे। जस्टिस संगम कुमार साहू के मुख्य न्यायाधीश बनने से न्यायिक कार्यों में गति और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायालय में लंबित मामलों के निपटान, न्याय की पहुंच और प्रशासनिक सुधारों में उनकी अनुभव और नेतृत्व की अहम भूमिका रहेगी। जस्टिस साहू का जन्म 1964 में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के नया बाजार हाई स्कूल से की और स्टीवर्ट विज्ञान कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और ओड़िया में एम.ए. की उपाधि हासिल की। उन्हें बचपन से ही न्याय और विधि के प्रति रुचि रही, जो उन्हें उनके पिता स्वर्गीय शरत चंद्र साहू से विरासत में मिली।

विदेश में नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी का खुलासा 349 पासपोर्ट के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार

एजेंसी। पटना

गोपालगंज में ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों बेरोजगार युवकों को ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 349 से ज्यादा पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह ठगी का एक संगठित और बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसकी जड़ें दूरदूर तक फैली हुई हैं। पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों को अपने जाल में फंसाता था। गुप्त सूचना के आधार पर हथुआ थाना क्षेत्र के मठिया गांव में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने आरोपी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया। छापेमारी का नेतृत्व थानाध्यक्ष शोएब आलम ने किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। भरोसा जीतने के बाद वह युवकों के पासपोर्ट, मोबाइल फोन, सीवी और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लेता था। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से लगभग 349 पासपोर्ट, कई मोबाइल फोन और दर्जनों सीवी बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस भी हैरान है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि ह्लहमें सूचना मिली थी कि हथुआ थाना क्षेत्र के मठिया गांव में एक व्यक्ति विदेश भेजने के नाम पर लोगों के पासपोर्ट अपने पास रखता है और फर्जी तरीके से विदेश भेजने का झांसा देता है। सूचना के सत्यापन के बाद हथुआ थानाध्यक्ष शोएब आलम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से सैकड़ों पासपोर्ट और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता।

बिहार में ठंड का कहर: तीन दिनों तक और बढ़ेगी कंपकंपी

शीतलहर जैसे हालात के आसार

एजेंसी। पटना

बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और आने वाले तीन दिन लोगों के लिए और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड की तीव्रता बढ़ेगी। खासकर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इसके चलते राज्य के अधिकांश जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर बिहार के मौसम पर पड़ रहा है। ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बनी रहने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। रात और सुबह के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में ठंड का असर अधिक देखने को मिल सकता है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय और छपरा समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। कुछ स्थानों पर तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। वहीं, सुबह के समय घना कोहरा छाने से दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि तापमान में तेज गिरावट के कारण शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। शीतलहर का सीधा असर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ सकता है। ठंडी हवाओं के कारण त्वचा, सांस और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने की आशंका है। ग्रामीण इलाकों में खुले में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है।

जनजीवन पर प्रभाव

ठंड बढ़ने से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सुबह-शाम सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि गरीब और बेघर लोगों के लिए ठंड सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ठंड के कारण बाजारों में भी सुबह के समय सन्नाटा पसरा रहता है।

सावधानी ही बचाव

मौसम विशेषज्ञों की मानें तो इस समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। पर्याप्त गर्म कपड़े पहनना, गर्म भोजन करना और अनावश्यक रूप से सुबह-शाम बाहर निकलने से बचना चाहिए। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ठंड से बचाकर रखना जरूरी है।

बिहार के 57 सब रजिस्ट्रार को इनकम टैक्स का नोटिस, जमीन रजिस्ट्री घोटाले में जांच तेज

एजेंसी। पटना

बिहार में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उत्तर बिहार में लगभग 95 प्रतिशत जमीन की रजिस्ट्री कैश में हो रही है, जिससे काले धन के प्रवाह की गंभीर आशंका जताई जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले की जांच के बाद बिहार के 57 सब-रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही 2,552 रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, जमीन रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। पैन कार्ड और फॉर्म-60 के बिना कई रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे इनकम टैक्स विभाग को वास्तविक लेन-देन की जानकारी नहीं मिल पा रही है। यही नहीं, इस प्रक्रिया का उपयोग ब्लैक मनी को खपाने के लिए भी किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे फॉर्म-60 का इस्तेमाल करके जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। फॉर्म-60 उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है और यह बैंक अकाउंट खोलने, निवेश करने और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जरूरी है। अगर यह फॉर्म सही तरीके से भरा नहीं जाता, तो रजिस्ट्रेशन करने वाले और खरीदने वाले दोनों के बारे में विभाग को कोई रिपोर्ट नहीं मिलती।